



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten signature and date: 31/7/97

सं० 292 ]  
No. 292]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 1997/आषाढ़ 25, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 1997/ASADHA 25, 1919

संचार मंत्रालय

(डब्ल्यू. पी. सी. पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1997

सा. का. नि. 393 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट, रिकार्डर सेट (अनुज्ञप्ति से छूट) नियम, 1985 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट, रिकार्डर सेट (अनुज्ञप्ति से छूट) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषा

2. इन नियमों में "प्रसारण उपग्रह सेवा" और "स्थिर उपग्रह सेवा" के वही अर्थ होंगे जो तत्समय प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के संविधान और कंवेशन से उपाबद्ध रेडियो विनियम में क्रमशः उनका समनुदेशित है।

कतिपय प्रसारण साधित्र के लिए अनुज्ञप्ति का अपेक्षित न होना

3. बेतार रिसीवर साधित्र अनुज्ञप्ति नियम, 1965, भारतीय बेतार तार यांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 या वाणिज्यिक प्रसारण रिसीवर अनुज्ञप्ति (व्यौहारी) नियम, 1965 में अन्तर्बिष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित को स्थापित करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यौहार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी :—

(i) रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट,

(ii) विशेष एन्टेना, जिसके अन्तर्गत डिश एन्टेना उपग्रह डिक्कोडर और सहयुक्त अग्रशिरा संपरिवर्तक भी है, का प्रयोग 4800 मेगा हर्ट्ज से कम के आवर्ती बैंडों में प्रसारण उपग्रह सेवा या स्थिर उपग्रह सेवा में क्रियाशील उपग्रह से सीधे स्थिर या चल वस्तुओं के अस्थायी बिम्बों का ग्रहण करने के लिए किया गया है या किया जा सकता है,

परन्तु खण्ड (ii) में निर्दिष्ट छूट अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप और मिनिक्कोय संघ राज्य क्षेत्रों में व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगी।

कतिपय बैंडों में साधित्र के प्रयोग का प्रतिषेध

4. नियम 3 और बेतार रिसीवर साधक अनुज्ञप्ति नियम, 1965 भारतीय बेतार तार यांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 या वाणिज्यिक प्रसारण रिसीवर अनुज्ञप्ति (व्यौहारी) नियम, 1965 में अन्तर्विष्ट किसी वस्तु के होते हुए भी कोई व्यक्ति विशेष एन्टेना जिसके अन्तर्गत डिश एन्टेना, उपग्रह डिक्कोडर और सहयुक्त अग्रशिरा संपरिवर्तक भी है, जिसका प्रयोग 4800 मेगा हर्ट्ज और अधिक के आवर्ती बैंडों में प्रसारण उपग्रह सेवा या स्थिर उपग्रह सेवा में सीधे स्थिर और चल वस्तुओं के स्थायी बिम्बों को ग्रहण करने के लिए किया गया है या किया जा सकता है स्थापित नहीं करेगा, उसका अनुरक्षण नहीं करेगा, उससे संबंधित कार्य नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं रखेगा या व्यौहार नहीं करेगा।

[सं. आर. 11014/7/97-एल. आर.]

एस. वेंकटसुब्रमण्यन, उप बेतार सलाहकार

**स्पष्टीकारक ज्ञापन :—**उपग्रह प्रसारण में एक नई प्रौद्योगिकी जो भारत में अब तक आरंभ नहीं हुई है और जो किसी उपग्रह प्रसारक को अंकीय संपीड़न और केयू बैंड ट्रांसपोंडर के उपयोग में समर्थ बनाती है। 4800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आवृत्ति बैंड में प्रेषण संकेतों को जिसे सीधे गृह (डी टी एच) प्रसारण सेवा कहा गया है, भारत की दहलीज पर है। इस समय "सी" बैंड ट्रांसपोंडर और 4800 मेगाहर्ट्ज से न्यून बैंड में आवृत्ति के उपयोग पर आधारित विद्यमान प्रौद्योगिकी के अधीन एक उपग्रह प्रसारक, एक केबल आपरेटर और ऐसे केबल आपरेटरों के माध्यम से ही सामान्यतया अपने कार्यक्रम वितरित करता है। किसी अवांछनीय और आपत्तिजनक कार्यक्रम का विनियमन संभव है किन्तु नई प्रौद्योगिकी के अधीन कोई उपग्रह प्रसारक उपग्रह के माध्यम से सीधे ही किसी कार्यक्रम को बहुत ही छोटे आकार के डिश एन्टेना की सहायता से उपग्रह से अपने कार्यक्रम भारत में सीधे दिखा सकता है जो जब कभी अपेक्षित हो, पता चलाने को भी चुनौती दे सकता है और इस प्रकार किसी मध्यवर्ती की अंतरवलिता के बिना जैसे केबल आपरेटर किसी मध्यवर्ती या विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमन कि किसी संभावना के बिना घरों से सीधा संपर्क स्थापित कर रहा है। संक्षेप में, नई प्रौद्योगिकी भारत के भीतर या बाहर किसी प्रसारक को अपनी पसंद के किसी कार्यक्रम को जन साधारण के घरों और शयन कक्षों तक सीधे प्रसारित करने या पहुंचाने में समर्थ बनाएगी। इस बात की आशंका है कि कोई प्रसारक जो भारत में अभिग्रहण के लिए डी टी एच सेवा आरंभ करने का विनिश्चय करता है, वह कार्यक्रम की प्रकृति या विषयवस्तु पर किसी नियंत्रण के बिना भारत की भूमि के बाहर से अपने सिग्नलों को जोड़ते हुए विदेशी संगठन को सम्मिलित कर सकेगा।

अतः, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा उपस्कर स्थापित करके उसका अनुरक्षण करने, उसके संबंध में कार्य करने, उस पर कब्जा रखने, या व्यौहार करने के लिए भारत में ऐसी डी टी एच सेवा आरंभ करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए जो भारत में डी टी एच सेवा से कार्यक्रमों के अभिग्रहण और प्रसारण को समर्थ बनाती है।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(WPC Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1997

**G.S.R. 393(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), and in supersession of the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 1985 the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

- |  |  |
|--|--|
| Short title and commencement.                            | 1. (1) These rules may be called the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 1997.<br>(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.   |
| Definition.  | 2. In these rules "Broadcasting Satellite Service" and "Fixed Satellite Service" shall have the meanings respectively assigned to them in the Radio Regulations annexed to the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, for the time being in force.  |
| Licence not required for certain broadcasting apparatus. | 3. Notwithstanding anything contained in the Licensing of Wireless Receiving Apparatus Rules, 1965, the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965 or the Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) Rules, 1965, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in —<br><br>(i) radio, television and video cassette recorder sets;<br>(ii) special antenna, including dish antenna, satellite decoder and associated front-end converter, used or capable of being used for reception of transient images of fixed and moving objects direct from satellites operating in Broadcasting Satellite Service or Fixed Satellite Service in frequency bands below 4800 MHz: |

Provided that the exemption referred to in clause (ii) shall not be available for persons in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura, and in the Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep and Minicoy Islands.

Prohibition  
for use of  
apparatus in  
certain bands.

4. Notwithstanding anything contained in rule 3 and the Licensing of Wireless Receiving Apparatus Rules, 1965, the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules 1965 or the Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) Rules, 1965, no person shall establish, maintain, work, possess or deal in special antenna, including dish antenna, satellite decoders and associated front-end converter used or capable of being used for reception of transient images of fixed and moving objects direct from satellites operating in Broadcasting Satellite Service or Fixed Satellite Service in frequency bands 4800 MHz and above.

[No. R-11014/7/97-LR]

S VENKATASUBRAMANIAN, Dy. Wireless Adviser

Explanatory Memorandum — A new technology in satellite broadcasting, not yet introduced in India, which enables a satellite broadcaster to use digital compression and Ku band transponders, transmitting signals in frequency band above 4800 MHz, (commonly called Direct To Home (DTH) broadcasting service) is on the threshold of entry into India. Presently a satellite broadcaster, under the existing technology based on use of a 'C' band transponder and frequencies in bands below 4800 MHz, normally distributes his programme only through a cable operator and through such cable operators, regulations of any undesirable and objectionable programme is feasible but under the new technology a satellite broadcaster can beam his programme directly from the satellite into Indian homes which can be received with the help of a very small sized dish antenna, which even defies detection if and when required and without the involvement of any intermediary like cable operator, thus establishing a direct link with house-holds without any possibility of regulation by an intermediary or any Regulatory Authority. In a nutshell, the new technology would enable any broadcaster within or outside India to telecast or beam any programme of his choice directly to the houses and bedrooms of general public. It is apprehended that any broadcaster who decides to start the DTH service for reception in India could include a foreign entity uplinking his signals from outside the Indian soil without any control over either the nature or content of the programme.

Therefore, it has become necessary to ensure that no person should be allowed to start such a DTH service in India by establishing, maintaining, working, possessing or dealing in any equipment that enables reception and dissemination of programmes from a DTH service in India.